Parimal Nathwani
Member of Parliament
(Rajya Sabha)

Member:
Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice
Consultative Committee, Ministry of Commerce and Industry
Permanent Special Invitee:
Consultative Committee, Ministry of External Affairs

165, South Avenue,
New Delhi - 110 011
Ph.: 011-23794010
e-mail : parimal.nathwani@sansad.nic.in

B/107, Harmu Housing Colony, P. O. Doranda,
P. S. Argora, Ranchi - 834 012
Ph. : 0651-2244144

प्रेस विज्ञप्ति

झारखण्ड की पंचायतों में कामकाज का कम्प्यूटरीकरण

इन्टरनेट क्नेक्टिविटी, बिजली, हार्डवेयर और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी धीमी प्रगति का कारण

पंचायती राज मंत्री का सांसद परिमल नथवाणी को उत्तर

रांची : अगस्त 11, 2012 : झारखण्ड में प्रिया सॉफ्ट और प्लान प्लस पर 300 से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। 380 पंचायत कर्मियों तथा निर्वाचित सदस्यों को मौलिक इन्फर्मेशन व कम्यूनिकेशन तक्नॉलॉजी साक्षरता में प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2011-12 के दौरान 23 जिला पंचायतों, 125 ब्लॉक पंचायतों तथा 2464 ग्राम पंचायतों ने प्रिया सॉफ्ट में वाऊचर एन्ट्रीज कीं; जब कि 9 जिला पंचायतों, 67 ब्लॉक पंचायतों तथा 1559 ग्राम पंचायतों ने प्लान-प्लस को अपनाया।

केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री श्री वी. किशोर चन्द्र देव ने राज्य सभा सांसद श्री परिमल नथवाणी के प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्य सभा को यह बताया। श्री नथवाणी ने जानना चाहा था कि पंचायतों में कामकाज के कम्प्यूटरीकरण के सम्बंध में सरकार की क्या नीति है और झारखण्ड में पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण की गति को तेज करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

श्री देव ने पंचायती राज मंत्रालय के अधीन कार्यान्वित ई-पंचायत मिशन मोड़ की विस्तृत जानकारी दी जिसके अंतर्गत 11 कोर कॉमन सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन्स नियोजित की गई हैं। इनमें से जो चार एप्लिकेशन्स लोगों की पहुंच में हैं वे हैं : प्रियासॉफ्ट, प्लान-प्लस, राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल तथा स्थानीय शासन निर्देशिका।

आपने बताया कि इन्टरनेट कनेक्टिविटी, पावर, हार्डवेयर की अनुपलब्धता तथा ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षित कर्मियों की अपर्याप्त संख्या पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण की धीमी प्रगति में कारणभूत हैं। आपने यह भी कहा कि योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के लिए कार्यशालाओं / प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है, 25 राज्यों को परियोजना का प्रसार आरंभ कराने के लिए कन्सल्टन्ट उपलब्ध कराए गए और वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य एवम् जिला स्तर पर प्रोग्राम मैनेजमेन्ट यूनिटों की स्थापना के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 38.5 करोड़ रुपए की धनराशि भी जारी की गई।

* * *